स्मार्ट भोजन कार्यकारिणी परिषद्

डाउन टू अर्थ, (20 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में "स्मार्ट भोजन कार्यकारिणी परिषद्" का गठन किया गया है, जिसमें एशिया-पैसिफिक एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस (APAARI), फोरम फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन अफ्रीका (FARA), वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीकन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डिवलपमेंट (CORAF), फूड एग्रीकल्चर एंड नेचुरल रिसोर्सेज पॉलिसी एनालिसिस नेटवर्क (FANRPAN) और अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंध क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) जैसे प्रतिष्ठान शामिल होंगे।
- यह वर्ष 2013 में आरम्भ की गई "स्मार्ट भोजन पहल" के अन्तर्गत है।

आवश्यकता क्यों पड़ी?

- इस परिषद् के गठन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज विश्व को ऐसे भोजन पदार्थों की जरूरत है जो न केवल उपभोक्ता और किसान के भले के लिए हो, अपितु इस धरती के लिए यह कल्याणकारी हो।

उद्देश्य

- यह परिषद् ऐसे अन्नों के उत्पादन पर बल देगी, जो पोषण से युक्त हों और साथ ही वातावरण एवं किसानों का कल्याण करें।

महत्व

- अनाज भोजन का 70% भाग होते हैं और इन्हें दिन में बहुधा तीन बार खाया जाता है। यदि इन अनाजों में विविधता लाई जाए, तो यह कुपोषण और गरीबी को दूर करने और जलवायु-परिवर्तन एवं पर्यावरण के क्षरण जैसी समस्याओं का सामना करने में सहायक हो सकती है।
- ऐसा करने से सतत् विकास लक्ष्यों के अंतर्गत गरीबी और भूख (SDG-1 और 2) को दूर करने, उत्तरदायी खपत और उत्पादन सुनिश्चित करने (SDG-12), जलवायु परिवर्तन से तालमेल करने (SDG-13), लैंगिक समानता लाने (SDG-5) और भागीदारी के माध्यम से काम करने (SDG-17) जैसे काम सिद्ध किये जा सकते हैं।

क्या है स्मार्ट भोजन पहल?

- स्मार्ट भोजन पहल (Smart Food initiative) अर्ध-शुष्क उष्णकटिबंध क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) के द्वारा आरम्भ की गई पहल है।
- इसका उद्देश्य भोजन की ऐसी प्रणाली का निर्माण करना है जिसमें उच्च पोषण हो, जो पृथ्वी का भला करने वाली हो और जिसमें छोटे किसानों की भलाई निहित हो।
- यह एक ऐसी पहल है जिसकी शुरुआत तरह-तरह के मोटे अनाजों को लोकप्रिय बनाने पर बल देने से की जायेगी।

दूसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश

द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस (20 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में भारत कच्चे तेल की मांग के मामले में वर्ष 2019 में चीन को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बन सकता है।
- यह अनुमान रिसर्च एंड कंसल्टेंसी ग्रुप वुड मैकेंजी ने लगाया है।
- रिसर्च एंड कंसल्टेंसी ग्रुप वुड मैकेंजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ऑटो ईंधन और एलपीजी की खपत में वृद्धि के कारण यह मांग बढ़ेगी।

मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2018 में भारत में तेल की मांग में जोरदार वृद्धि हुई है। जीएसटी और नोटबंदी लागू होने के बाद इसने वैश्विक मांग में 14 फीसदी या 2.45 लाख बैरल प्रतिदिन (बीपीडी) का योगदान दिया है।

- रिपोर्ट में वर्ष 2019 में समान स्तर पर तेल की मांग बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है इसका परिणाम यह होगा कि भारत 2019 में चीन को पछाड़कर तेल की मांग वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन जाएगा। फिलहाल, इस मामले में अमेरिका पहले पायदान पर है।
- गौरतलब है कि भारत ने वित्त वर्ष 2017-18 में 20.62 करोड़ टन तेल का उपभोग किया था। अप्रैल-दिसंबर के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की खपत 15.74 करोड़ टन रही है, जो पिछले साल की तुलना में 2.5 फीसदी अधिक है।
- अमेरिकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (ईआईए) के अनुसार, भारत वर्तमान में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है।

भारत में डीजल की खपत सबसे अधिक

- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में डीजल की खपत सबसे अधिक है। वर्ष 2019 में यह वर्ष 2018 के 93,000 बीपीडी के मुकाबले 6.4 फीसदी बढ़कर 1.12 लाख बीपीडी हो जाएगा।
- ओपेक (Organization of the Petroleum Exporting Countries) ने वर्ष 2040 तक भारत में तेल की मांग बढ़कर 58 लाख बीपीडी होने का अनुमान लगाया था।

प्रवासी भारतीय दिवस

इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैण्डर्ड, (21 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस का 15वाँ संस्करण 21 जनवरी, 2019 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हो गया है।
- प्रवासी भारतीय दिवस (Pravasi Bhartiya Divas, 2019) के लिए इस बार वाराणसी में बेहद खास आयोजन किया गया है।
- प्रवासी भारतीय दिवस समारोह वाराणसी में 21 से 23 जनवरी तक चलेगा।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 जनवरी, 2019 को वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
- पहली बार वाराणसी में 21 से 23 जनवरी, 2019 तक तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

15th 2019
प्रवासी भारतीय दिवस
PRAVASI BHARATIYA DIVAS

मुख्य अतिथि

- मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 15वें संस्करण के मुख्य अतिथि होंगे।
- नॉर्वे के सांसद हिमांशु गुलाटी विशिष्ठ अतिथि और न्यूजीलैण्ड के सांसद कंवलजीत सिंह बक्शी सम्मानित अतिथि होंगे।

उद्देश्य और विषय

- प्रवासी भारतीय दिवस का मकसद भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को पहचान दिलाने से है।
- प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2019 का विषय है- नये भारत के निर्माण में भारतीय प्रवासियों की भूमिका।

प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करना

- इस सम्मेलन में विदेश में रह रहे उन भारतीयों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल कर भारत का नाम विश्व पटल पर गौरवान्वित किया हो।
- देश का नाम रोशन करने वाले ऐसे लोगों को राष्ट्रपति के हाथों प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा जाता है।
- इसके अलावा इस सम्मेलन में प्रवासी भारतीयों से जुड़े मामलों और समस्याओं पर भी विचार किया जाता है।
- यह प्रवासी भारतीय दिवस का 15वां आयोजन है, इससे पहले

प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 9 जनवरी को या उसके आस-पास होता आया था।

- सम्मेलन के बाद प्रतिभागी 24 जनवरी को कुंभ मेले में शामिल होने के लिए प्रयागराज की यात्रा करेंगे।

क्या है प्रवासी भारतीय दिवस?

- प्रवासी दिवस की शुरुआत वर्ष 2003 से हुई थी।
- इस मौके पर हर साल भारत सरकार अमूमन तीन दिवसीय सम्मेलन का आयोजन करती है। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का निर्णय लिया था।
- पहले प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 9 जनवरी, 2003 को नई दिल्ली में हुआ था।
- प्रवासी भारतीय दिवस के आयोजन के लिए 9 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि वर्ष 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आये थे।
- यह आयोजन विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय को सरकार के साथ काम करने और अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने का मंच उपलब्ध कराता है।
- सम्मेलन के दौरान भारत और विदेश दोनों में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले चुने गये भारतीय प्रवासियों को प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किये जाते हैं।

संविधान की 10वीं अनुसूची

द हिन्दू, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, (21 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में पंजाब विधानसभा ने AAP पार्टी के बागी MLA सुखपाल सिंह खैरा (भोलथ विधानसभा) को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य घोषित करने के लिए नोटिस निर्गत किया है।
- 6 जनवरी को खैरा ने AAP पार्टी से त्यागपत्र दे दिया था, परन्तु विधायक पद को छोड़ा नहीं था। आगे चलकर उन्होंने एक नई पार्टी भी बना ली थी।

संविधान की दसवीं अनुसूची क्या है?

- राजनीतिक दल-बदल लम्बे समय से भारतीय राजनीति का एक रोग बना हुआ था और 1967 से ही राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक (anti-defection law) लगाने की बात उठाई जा रही थी।
- अन्ततोगत्वा आठवीं लोकसभा के चुनावों के बाद 1985 में संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से 52वाँ संशोधन पारित कर राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगा दी। इसे संविधान की दसवीं अनुसूची (10th Schedule) में डाला गया।

कब होती है सदस्यता समाप्त?

- यदि वह स्वेच्छा से अपने दल से त्यागपत्र दे दे।
- यदि वह अपने दल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना सदन में उसके किसी निर्देश के प्रतिकूल मतदान करे या मतदान में अनुपस्थित रहे।
- परन्तु यदि 15 दिनों, उपर्युक्त परिस्थितियों (conditions) में संसद या विधानसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, के अन्दर दल उसे इस उल्लंघन के लिए क्षमा कर दे तो उसकी सदस्यता (membership) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

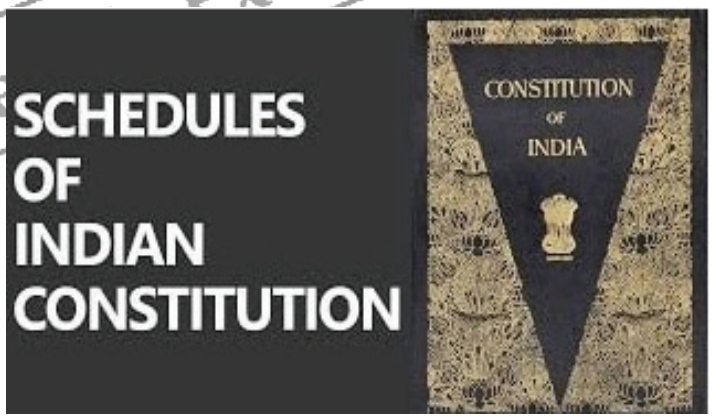

कब बनी रहेगी सदस्यता?

- निम्न परिस्थितियों (conditions) में संसद या विधानसभा के सदस्य की सदस्यता बनी रहेगी -
- यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य (Independent Member)

किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाये।

- यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के बाद 6 माह की अवधि में किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाये।
- किसी राजनीतिक दल के विलय (merger) पर सदस्यता समाप्त नहीं होगी, यदि मूल दल में कम-से-कम 2/3 सांसद/विधायक दल छोड़ दें।
- यदि लोकसभा/विधानसभा का अध्यक्ष (speaker) अपना पद छोड़ देता है तो वह अपनी पुरानी पार्टी में लौट सकता है, इसको दल-बदल नहीं माना जायेगा।

ReWeave परियोजना

फाइनेंसियल एक्सप्रेस, बिजनेस टुडे, (21 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने हथकरघा बुनकरों को सहायता पहुँचाने के लिए ReWeave परियोजना के अन्दर एक नए ई-वाणिज्य मंच का अनावरण किया है। जिसका नाम 're-weave-in' रखा गया है।

उद्देश्य

- कारीगरों को खरीदने वालों से सीधे जोड़ना जिससे कि वे नए-नए ग्राहकों और बाजारों तक पहुँच सकें।
- बुनकर समुदायों द्वारा बनाए गये उत्तम कपड़ों को विश्व के सामने रखना।

- प्राकृतिक रंगों से तैयार किये गये पारम्परिक शैलियों और उत्पादों को अधिक से अधिक ग्राहकों के समक्ष रखना।
- बुनकरों को अपनी आय बढ़ाने में तथा उनकी सतत् आजीविका के लिए उन्हें सहायता पहुँचाना।
- भारत की भूली-बिसरी पारम्परिक कला को फिर से जीवित करना।

क्या है?

- यह परियोजना 2016 में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया (R&D) प्रा.लि. के द्वारा अपनी मानव कल्याण योजना के तहत शुरू की गई थी।
- इसके तहत भारत में हथकरघा बुनाई के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना है।
- इस पहल के तहत माइक्रोसॉफ्ट गैर-सरकारी संगठन चैतन्य भारती के साथ मिलकर बुनकर परिवारों को आवश्यक अवसंरचना, वित्त एवं बाजार की सुविधा प्रदान करता है।

पर्यावरणिक 'टाइम-बम'

बिजनेस स्टैण्डर्ड, (22 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरणिक "टाइम-बम" का सामना करना पड़ेगा क्योंकि संसार की भूमि जल प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए आज जो कदम उठाये जा रहे हैं उनका असर आने में कई दशक लग सकते हैं।

समस्या क्या है?

- एक अंतर्राष्ट्रीय शोध-दल के निष्कर्षों के अनुसार एक तरफ जहाँ वैश्विक जनसंख्या में विस्फोट हो रहा है और साथ ही साथ फसल उत्पादन में वृद्धि हो रही है, वहीं दूसरी ओर भूमि-जल के भंडारों का दोहन भी बढ़ रहा है।
- भूमि-जल को फिर से पहले के स्तर तक पहुँचने में सूखा आड़े आता है और अति-वर्षा का भी इस पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

संकट का नाम टाइम-बम क्यों?

- शोधकर्त्ताओं का कहना है कि अगले सौ वर्षों में हमारे भूमि-जल की आधी ही मात्रा फिर से लौट सकेगी। इससे शुष्क क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या उत्पन्न हो जायेगी।
- इसलिए इस समस्या को टाइम-बम का नाम दिया गया है अर्थात् एक लम्बे समय के पश्चात् इसका सबसे विकट रूप सामने आएगा।

भारत में भूजल की स्थिति

- भारत विश्व में सर्वाधिक भूजल का प्रयोग करता है।
- यहाँ भूजल का 90% पीने के लिए प्रयुक्त होता है। सिंचाई का 60-70% जल भी भूजल से ही आता है। शहरों में पानी की 50% आपूर्ति भी भूजल से ही होती है।

भूजल संकट के दो मुख्य कारण

- जलाशयों का अतिशय दोहन।
- भूमि जल का प्रदूषण :- यह प्रदूषण आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे भूगर्भीय पदार्थों के कारण तो होता ही है, इसके लिए कचरे और अपशिष्ट जल का सही निपटारा नहीं होना भी एक प्रधान कारण है।

साइज इंडिया परियोजना

बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस, (21 Jan.)

संदर्भ

- फरवरी, 2019 में "साइज इंडिया" परियोजना पर भारतीय कपड़ा निर्माता संघ (Clothing Manufacturers Association of India – CMAI) केन्द्रीय कपड़ा मंत्रालय के साथ मिलकर काम आरम्भ करने जा रहा है।
- इसके लिए CMAI पूरे भारतवर्ष में भ्रमण कर कपड़ों के मानक नापों का निर्धारण करेगा।

क्या है?

- साइज इंडिया परियोजना कपड़ा और परिधान उद्योग के लिए ऐसी नाप सूची तैयार करेगी जो विशेषकर भारतीय प्रयोग के अनुकूल होगी।
- इस परियोजना का उद्देश्य परिधानों के लिए भारतीय नाप का मानक तय करना है। इस परियोजना से परिधानों के दाम कम हो जाएँगे और उपभोक्ता इससे लाभान्वित होंगे।

मुख्य बिंदु

- इस परियोजना के अन्दर भारत के छह बड़े नगरों में जाकर 15 से 65 वर्ष आयु-वर्ग के लोगों के 25,000 नमूने जमा किये जाएँगे और उनसे नाप से सम्बंधित डाटा जमा किया जायेगा। इन नमूनों में आधे नमूने पुरुषों के और आधे स्त्रियों के होंगे।
- इस डाटा के आधार पर एक मानकीकृत नाप चार्ट तैयार किया जाएगा जो भारतीय लोगों के अनुसार होगा और जिसके अनुसार परिधान उद्योग कपड़े तैयार करेगा।

मानक नाप आवश्यक क्यों?

- परिधानों का खुदरा बाजार भारत के आज के खुदरा बाजार की एक बहुत बड़ी शक्ति है क्योंकि इसमें 72 बिलियन डॉलर का व्यापार चलता है।
- अमेरिका और इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में परिधानों के लिए मानकीकृत नाप चलते हैं। इससे ग्राहकों को दुकान पर अथवा ऑनलाइन कपड़े खरीदते समय संतोष होता है और परिधान निर्माता अनावश्यक कपड़ा बनाने से बच जाते हैं।
- आजकल अधिकांश लोगों को ऐसे कपड़े खरीदने में कठिनाई आती है जो उनके शरीर पर पूरी तरह फिट आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस देश में अलग-अलग भूभागों में लोगों की शारीरिक बनावट अलग-अलग होती है।

स्टेट्स पेपर

द हिन्दू, (22 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में केंद्र सरकार ने 2017-18 का सरकारी ऋण से सम्बंधित स्टेट्स पेपर निर्गत किया है।

मुख्य बिंदु

- जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्र का समग्र ऋण 2017-18 में घटकर 46.5% हो गया है जबकि 31 मार्च, 2014 में यह प्रतिशत 47.5 था।
- राज्यों का समग्र ऋण 2017-18 में बढ़कर 24% हो गया और यह संभावना है कि यह 2018-19 में 3% हो जाए।

- कुल मिलाकर केंद्र का ऋण 2017-18 में 45% बढ़कर 82,35,178 करोड़ रू. हो गया है, जबकि मार्च, 2014 के अंत में 56,69,429 करोड़ रू. था।
- जहाँ तक राज्यों की बात है उनका समग्र ऋण इसी अवधि में 24,71,270 करोड़ रू. से 63% बढ़कर 40,22,090 करोड़ रू. हो गया।

समीक्षा

- एन.के. सिंह समिति की सार्वजनिक ऋण विषयक अनुशंसाओं के हिसाब से केंद्र सरकार सही दिशा में जा रही है।
- लेकिन राज्य इस मामले में उल्टी दिशा में चल रहे हैं। इनका बकाया दायित्व 2015-16 और 2016-17 के दौरान UDAY बाँडों के निर्गम के पश्चात् बहुत तेजी से बढ़ा है।
- राज्य-स्तर पर ऋणों में वृद्धि चिंताजनक है क्योंकि यदि यह वृद्धि एक विशेष सीमा को पार कर जायेगी तो ऋण चुकाने के लिए राज्यों के पास समुचित साधन नहीं होंगे और वे ऋणों के जाल में फँसते चले जाएँगे।

एन.के. सिंह समिति की अनुशंसाएँ

- इस समिति का सुझाव था कि 2023 तक ऋण का अनुपात केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20% तक सीमित हो जाना चाहिए।
- समिति का कहना था कि यही अनुपात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट अनुपात माना जाता है। यदि यह अनुपात बनाया रखा जाएगा, तो साख की रेटिंग करने वाली एजेंसियाँ बेहतर रेटिंग देंगी।

कार्य के भविष्य से सम्बंधित वैश्विक आयोग

बिजनेस टुडे, (22 Jan.)

संदर्भ

- हाल ही में कार्य के भविष्य से सम्बंधित वैश्विक आयोग (Global Commission on the Future of Work) ने 22 जनवरी, 2019 को अपना प्रतिवेदन निर्गत कर दिया है।
- इस प्रतिवेदन में सरकारों से आह्वान किया गया है कि वे कार्य-जगत में हो रहे अभूतपूर्व रूपान्तरणों के फलस्वरूप उभरने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाएँ।

प्रतिवेदन के सुझाव

- कामगारों को उचित मजदूरी मिले, उनके काम के घंटे सीमित हों और उनके काम करने की जगह सुरक्षित और स्वास्थ्यकर हो।
- जन्म से लेकर बुढ़ापे तक सभी को सामाजिक सुरक्षा मिले।
- सभी को जीवन-भर ऐसा कुछ सीखने को मिले कि वे कौशल का अर्जन कर सकें और उसमें संवर्धन करते जाएँ।
- तकनीकी साधनों से अच्छे कार्य को बढ़ावा मिले और इसके लिए डिजिटल श्रम मंचों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन-तन्त्र हो।
- केयर, ग्रीन और ग्रामीण अर्थव्यस्थाओं में अधिक-से-अधिक

निवेश हो।

- लैंगिक समानता के लिए एक रूपांतरकारी और आकलनीय कार्यसूची तैयार की जाए।
- व्यावसायिक उत्प्रेरणाओं को इस तरह नया रूप दिया जाए जिससे कि दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहन मिले।

यह आयोग क्या है?

- यह आयोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का एक अंग है।
- इसका उद्देश्य कार्य के भविष्य की गहरी पड़ताल करना है जिससे कि 21वीं शताब्दी में सामाजिक न्याय देने के लिए आवश्यक विश्लेष्णात्मक आधार उपलब्ध हो सके।
- यह आयोग कार्यजगत के द्वारा सामना कर रही बड़ी-बड़ी चुनौतियों का पता भी लगाता है और इनके समाधान के लिए व्यावहारिक सुझाव भी देता है।

संबंधित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में 'स्मार्ट भोजन कार्यकारिणी परिषद्' का गठन किया गया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसके अंतर्गत 'स्मार्ट भोजन पहल' की शुरूआत की गयी है।
2. यह परिषद् पोषणयुक्त अन्नों के उत्पादन पर बल देगी।
3. स्मार्ट भोजन पहल अर्द्धशुष्क उष्णकटिबंध क्षेत्र के लिए आरम्भ की गई पहल है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 3
(c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

2. रिसर्च एंड कंसल्टेंसी ग्रुप वुड मैकेंजी ने तेल की माँग में वृद्धि पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2019 में विश्व का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश बन जाएगा।
2. भारत में डीजल की खपत सबसे अधिक है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

3. हाल ही में चर्चा में रहे 'प्रवासी भारतीय दिवस' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. प्रवासी भारतीय दिवस के 15वें संस्करण का शुभारम्भ 21 जनवरी, 2019 को वाराणसी में किया गया।
2. 9 जनवरी, 1915 को महात्मा गाँधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने की स्मृति में प्रवासी भारतीय दिवस की शुरूआत 2003 में हुई थी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

4. संविधान की 10वीं सूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. 52वाँ संविधान संशोधन, 1985 पारित कर राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक के प्रावधान को 10वीं अनुसूची में डाला गया है।
2. यदि लोकसभा/विधानसभा का अध्यक्ष अपना पद छोड़ देता है, तो वह अपनी पुरानी पार्टी में लौट सकता है, इसको दल-बदल नहीं माना जाएगा।
3. यदि सांसद/विधायक अपने दल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना सदन में उसके किसी निर्देश के प्रतिकूल मतदान करे या मतदान में अनुपस्थित रहे, तो उसकी सदस्यता बनी रहेगी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 2 (b) केवल 3
(c) 1 और 2 (d) 1, 2 और 3

5. 'ReWeave परियोजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह परियोजना माइक्रोसॉफ्ट इंडिया (R&D) प्रा.लि. द्वारा शुरू की गयी।
2. इसका उद्देश्य बुनकर परिवारों को आवश्यक संरचना, वित्त एवं बाजार की सुविधा प्रदान करना है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन असत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

6. हाल ही में वैज्ञानिकों ने भूजल के गिरते स्तर को देखते हुए 'पर्यावरणिक टाइम-बम' पद का उल्लेख किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. अगले सौ वर्षों में हमारे भूमि जल की आधी ही मात्रा फिर से लौट सकेगी। इससे शुष्क क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
2. भूमि जल का प्रदूषण आर्सेनिक और फ्लोराइड जैसे भूगर्भीय पदार्थों के कारण होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

7. 'साइज इंडिया परियोजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को 2030 तक दोगुना करना है।

GS World
Committed To Excellence

2. यह परियोजना भारतीय कपड़ा निर्माता संघ तथा केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के साझे प्रयास द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

8. हाल ही में केंद्र सरकार ने 2017-18 का सरकारी ऋण से सम्बंधित स्टेट्स पेपर निर्गत किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एन.के. सिंह समिति की सार्वजनिक ऋण विषयक अनुशंसाओं के अनुसार केंद्र सरकार विपरीत दिशा में चल रही है, जबकि राज्य सही दिशा में।
2. इस समिति का सुझाव था कि 2023 तक ऋण का अनुपात केंद्र एवं राज्यों के लिए 60:40 तक सीमित हो जाना चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

9. 'कार्य के भविष्य से सम्बंधित वैश्विक आयोग' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. यह आयोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक अंग है।
2. इस आयोग ने हाल ही में अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया कि केयर, ग्रीन और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं में अधिक से अधिक निवेश होना चाहिए।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

नोट : 17-19 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(d), 2(b), 3(a), 4(d), 5(d), 6(d) होगा।

GS World
Committed To Excellence